गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 261
दि. 22.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगा 'फेज्ड बैटल एरे' व भैरव लाइट कमांडो बटालियन करेगी ऐतिहासिक डेब्यू

भैरव लाइट कमांडो बटालियन का ऐतिहासिक डेब्यू

नई दिल्ली, (जीएनएस)। भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर एक नए अवतार में दिखाई देगा। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड न केवल 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद पहली बड़ी सैन्य प्रदर्शनी है, बल्कि यह भारतीय सेना की बदलती युद्ध रणनीति का गवाह भी बनेगी।

इस बार का मुख्य आकर्षण सेना का "फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन" होगा। इसके जरिए दुनिया पहली बार भारतीय सेना को युद्ध के वास्तविक अंदाज में मार्च करते देखेगी। इसके साथ ही, हाल ही में गठित 'भैरव लाइट कमांडो बटालियन' का डेब्यू और वंदे मातरम् के 150 वर्षों का उत्सव इस समारोह को ऐतिहासिक बना देगा।

यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी और 'VVIP' कल्चर के खात्मे जैसे बड़े बदलावों के साथ, यह परेड विकसित भारत की एक नई और सशक्त तस्वीर पेश करने के लिए तैयार है।

भारतीय सेना ने इस साल परेड की पारंपरिक शैली को बदलकर इसे पूरी तरह युद्ध जैसे क्रम में ढाल दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को यह दिखाना है कि वास्तविक युद्ध क्षेत्र में सेना किस तरह आगे बढ़ती है:

रणनीतिक क्रम: परेड में सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाने वाली टुकड़ियां चलेंगी।

हमलावर दस्ता: इसके पीछे भारी हथियारों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लैस मुख्य लड़ाकू यूनिट्स होंगी।

लॉजिस्टिक सपोर्ट: अंत में सेना की रसद, संचार और चिकित्सा सहायता वाली सपोर्ट यूनिट्स दिखाई देंगी।

युद्ध गियर: सैनिक इस दौरान

केवल औपचारिक वर्दी में नहीं, बल्कि अपने पूर्ण युद्ध उपकरणों और हथियारों के साथ नजर आएंगे।

भैरव लाइट कमांडो बटालियन का ऐतिहासिक डेब्यू

इस साल कर्तव्य पथ पर पहली बार 'भैरव लाइट कमांडो बटालियन' के जवान कदमताल करेंगे। इस विशेष यूनिट का गठन सामान्य पैदल सेना और हाई-प्रोफाइल स्पेशल फोर्सेज के बीच के अंतर को भरने के लिए किया गया है। यह बटालियन अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए तैयार की गई है।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दिखेगा संदेश

यह परेड पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में की गई सीमा पार सटीक सैन्य कार्रवाई, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली राष्ट्रीय परेड है। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय सेना के मनोबल और मारक क्षमता को एक नई पहचान दी है।

जिसकी झलक इस बार के सैन्य प्रदर्शन और हथियारों के चयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

आसमान से जमीन तक स्वदेशी ताकत

भारत अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन आसमान और जमीन दोनों पर करेगा:

फ्लाईपास्ट: राफेल, सुखोई-30, मिग-29, और पी-8आई जैसे लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे, एलसीएच (LCH), और एमआई-17 हेलिकॉप्टर विशेष फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे।

जमीनी हथियार: स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, एटीएजीएस (ATAGS), धनुष तोप, और 'शक्तिबाण' के साथ आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा।

वंदे मातरम् के 150 साल और 'नदियां' बनीं पहचान

सांस्कृतिक गौरव: इस साल की थीम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर आधारित है, जिसे दुर्लभ चित्रों और कलाकृतियों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा।

VVIP कल्चर का अंत: सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए 'VVIP' शब्द को हटा दिया है। अब बैठने के स्थानों के नाम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी भारतीय नदियों पर रखे गए हैं।

बीटिंग द रिट्रीट: 29 जनवरी के कार्यक्रम में एनक्लोजर के नाम बांसुरी, तबला और सरोद जैसे वाद्य यंत्रों पर होंगे।

Republic Day: कौन होंगे इस बारे के मुख्य अतिथि?

इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे। यह उपस्थिति भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों की मजबूती का संकेत है।

यूपी: पीठासीन सम्मेलन में बोले सीएम योगी- पीठ द्वारा विपक्ष को ज्यादा मौका देने पर नाराज नहीं होती सरकार

लखनऊ, (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा मंडप में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया।

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पीठ और सरकार की सोच प्रोएक्टिव (सक्रिय पहल की) होती है, रिएक्टिव (प्रतिक्रियावादी) नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती।

योगी ने कहा कि पीठ पक्ष-विपक्ष में संतुलन बनाती है। सीएम ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। सीएम ने ऐसे सम्मेलनों को सीखो-सिखाओ का मंच बताया। योगी ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है।

न्याय, समता, बंधुता लोकतंत्र की आत्मा

उन्होंने कहा कि संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।

संसद हम सबके लिए प्रेरणा

पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा व विधान परिषद, संसद के नियमों-परिनियमों की जानकारी ले लें तो सदन संचालन में काफी आसानी होगी।

सीएम ने कहा, सतीश महाना ने

विधानमंडल लोकतंत्र की नींव अंतिम व्यक्ति की आवाज तक है पहुँचता : सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विधानमंडल लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और इसके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुँचती है। मुख्यमंत्री ने यह बात 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और विधायी निकायों के सचिवों के 62वें सम्मेलन के समापन सत्र में कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के विधानमंडल न केवल कानून बनाने में बल्कि समावेशी और व्यापक विकास के लिए नीतियां बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, 'विधानमंडल लोकतंत्र की मूलभूत इकाई है।

उपराष्ट्रपति ने कहा - विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारत पर अपनी शर्तें न थोपे

उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु स्थित सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती समारोह में राष्ट्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया

उपराष्ट्रपति ने कहा - भारत प्रौद्योगिकी सृजनकर्ता के रूप में उभर रहा है

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु स्थित सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और संस्थान को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों की विशिष्ट सेवा पूरी करने पर बधाई दी।

उपराष्ट्रपति ने रजत जयंती समारोह को केवल समय के साथ संस्थान का बढना नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, दृढ़ता और उद्देश्य परक यात्रा बताया। उन्होंने सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के मूल मान्यता संबंधी प्रतिबद्धता की सराहना की कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और नैतिकता पूर्ण प्रणेता भी तैयार करना है। उन्होंने संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद-एनएएसी द्वारा सर्वोच्च ए++ ग्रेड मान्यता दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने संस्थान के इनक्यूबेशन सेंटर और सभागार का भी उद्घाटन किया।

राज्यपाल पद के अपने कार्य अनुभव का स्मरण करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के श्रेणी निर्धारण और गुणवत्ता में सुधार पर लगातार जोर दिया था। उन्होंने कहा कि संस्थानों की खराब श्रेणी अक्सर शिक्षकों के रिक्त पदों की वजह से होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों की अच्छी संख्या शैक्षणिक मानक, विश्वसनीयता और जनविश्वास प्रत्यक्ष रूप से बढाती है।

श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सलाह दी कि वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और दूसरों से अपनी तुलना किए बिना अपनी गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें।

उन्होंने कहा कि भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता, लेकिन कड़े परिश्रम और सत्यनिष्ठा से सफलता अवश्य मिलती है, भले ही यह तुरंत न मिले, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ मिलती ही है।

भारत के नवाचार-संचालित विकास का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश अब केवल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी सृजनकर्ता के रूप में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने स्मरण कराया कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों से इससे निपटने के लिए औषधि विकसित करने का आह्वान किया था, तब देश ने चुनौती का सामना करते हुए सफलतापूर्वक स्वदेशी टीके विकसित किए, जो भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल का उल्लेख करते हुए श्री राधाकृष्णन ने सीएमआरआईटी की सराहना की, जिसने नवोन्मेष और इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा 50 से अधिक स्टार्टअप उद्यों को बढ़ावा देकर जीवंत और मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में योगदान दिया है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थान युवाओं के मार्गदर्शक होते हैं और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक सुदृढ और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है, न कि अन्य देशों पर शर्तें थोपना, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कभी भारत पर शर्तें न थोप सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र की शक्ति आत्मनिर्भरता, ज्ञान, नवाचार और नैतिक आत्मविश्वास पर आधारित होनी चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करती है, बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और लोकाचार में गहराई से निहित है।

उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को हर प्रकार की लत से दूर रहने और मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति सतर्क रहने को कहा। उन्होंने युवाओं से नशीली दवाओं को ना कहने और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, ऋषिकेश और हरिद्वार में जानिए क्यों खास है कार्यक्रम

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह के 21 और 22 जनवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर हरिद्वार और देहरादून जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। वीवीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर शहर और आसपास के मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू रहेगा।

शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह हरिद्वार और ऋषिकेश में आयोजित कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

उनके इस दौरे को राज्य के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। सबसे पहले अमित शाह स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन पहुंचेंगे, जहां गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक

पत्रिका 'कल्याण' के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में शिरकत की।

22 जनवरी को अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे पतंजलि योगपीठ स्थित महर्षि दयानंद ग्राम में होगा, जहां वह पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इसके बाद सुबह 10:45 बजे वह हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचेंगे, जहां वह 'अखंड ज्योति' के दर्शन करेंगे और गायत्री परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।

इसके बाद सुबह 11:15 बजे अमित शाह बैरागी द्वीप, हरिद्वार में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

इस 'शताब्दी वर्ष समारोह 2026' में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल होने की संभावना है। अमित शाह इस अवसर पर अपने विचार भी साझा करेंगे और गायत्री परिवार के सामाजिक व आध्यात्मिक योगदान की सराहना करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक सम्पन्न

वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया एवं वन राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी बैठक में उपस्थित रहे

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जेसोर अभयारण्य को भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया

मुख्यमंत्री के संरक्षित वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस बनाने के दिशानिर्देश

गांधीनगर, 21 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक में जानकारी दी गई कि बनासकांठा के जेसोर भालू अभयारण्य को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत

विवरण में यह भी बताया गया कि रतनमहल अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी देखी गई है और वहां उसके स्थायी रूप से बसने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस संदर्भ में एनटीसीए की सहभागिता से इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण एवं देखभाल के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को देने की योजना पर भी इस बैठक में सार्थक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वन विभाग को राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों/विजिटर्स की बढ़ती संख्या के कारण वन्यजीव जगत को किसी भी प्रकार का नुकसान या व्यवधान न हो, इसकी विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में इस उद्देश्य से इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करने के दिशानिर्देश दिए। इस बैठक में गुजरात में तेंदुओं की बढ़ती संख्या तथा रेस्क्यू किए गए तेंदुओं सहित तेंदुओं के लिए निकट भविष्य में अभयारण्य स्थल सुनिश्चित करने की योजना पर भी चर्चा की गई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी के समक्ष अभयारण्य/नेशनल पार्क में सड़क-रास्ते, जल आपूर्ति, ऑप्टिकल फाइबर, रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन आदि से संबंधित लगभग 18 विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए।

विधायकगण सर्वश्री महेश कसवाला, देवाभाई मालम, मालतीबेन महेश्वरी आदि ने सहभागिता करते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक का संचालन वन्य प्राणी जगत के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डॉ. जयपालसिंह ने किया।

इस बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स डॉ. ए. पी. सिंह सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार के सहारे युद्ध में फंसते देश

रूस और चीन की मीडिया ने भी इसे ईंरान विरोधी प्रोपेगंडा व पामिमी दुष्प्रचार बताया। जबकि ठीक इसके विपरीत पूरे ईंरान में लाखों लोग वर्तमान ईंरानी सत्ता खासकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेईं के समर्थन में व अमेरिका-इजरायल के विरोध में सड़कों पर उतरे। कलयुग के ये सबल हथियार - झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी का राजधानी कोराकस से गत 3 जनवरी कोअपहरण कर ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देने के नाम पर जिसतरह उन्हें न्यूयॉर्व ले जाया गया और उसके फ ौरन बाद जिस तरह ईंरान पर अमेरिकी हमले की भूमिका तैयार करने के लिये ईंरान में पिछले दिनों चले कथित सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को प्रचारित व प्रसारित किया गया इन घटनाओं इनसे जुड़ी ज़मीनी सच्चाईं ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या अब यह दुनिया पूरी तरह से झूठ,अफ वाह व दुष्प्रचार की गिरफ़्त में आ चुकी है? क्या आज की दुनिया में झूठ, दुष्प्रचार और अफ वाहें बहुत बड़ी ताक त बन चुकी हैं। इतनी बड़ी ताक त कि इनके बल पर कहीं चुनाव परिणाम भी उलट सकते हैं? अपने देश के विपक्ष या किसी देश की सत्ता को बदनाम किया जा सकता है? कहीं गृह युद्ध की आग भड़काईं जा सकती है? इसी के बल पर किसी देश को परमाणु हथियार रखने वाला तो किसी को केमिकल हथियार रखने वाला देश बताकर उस देश को ही तहसनहस किया जा सकता है? किसी स्वाभिमानी देश या शासक को नीचा दिखाने के लिये उसे तानाशाह या जनविरोधी वुछ भी बताकर वहां खूनी इबारत लिखी जा सकती है? निति रूप से झूठ, अफ वाह और दुष्प्रचार सत्ता व राजनीति का हमेशा से ही प्रबल हथियार रहा है। खुद जर्मन तानाशाह हिटलर इसे एक प्रभावी हथियार मानता था। हिटलर का मानना था कि हमेशा एक ही बात को दोहराओ, चाहे वो कितनी भी सरल क्यों न हो। वह कहता था कि प्रोपेगैंडा में सच्चाईं को थोड़ा-सा मिलाकर झूठ को और प्रभावी बनाया जा सकता है। और उसी का मत यह भी था कि झूठ इतना बड़ा होना चाहिए कि कोईं सोचे भी नहीं कि कोईं इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। खुद हिटलर ने इसी नीति का इस्तेमाल यहूदियों के विरुद्ध कर दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार अंजाम दे डाला। इसी तरह 2002-2003 का वह दौर याद कीजिये जब अमेरिका ने तत्कालीन इराक ी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियार और अन्य सामूहिक विनाश के हथियार रखने का गंभीर आरोप लगाया था। इस आरोप को अमेरिका ने इतना प्रचारित किया था कि इसी आधार पर मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला तक कर दिया। सद्दाम को अपदस्थ कर उसे सामूहिक हत्या के दूसरे मामले में फांसी के पंदे पर चढ़ा दिया। बाद में रिपोर्ट आईं कि इराक के पास कोईं सव्रिय या बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का भंडार नहीं मिला। कोईं रासायनिक हथियार उत्पादन, कोईं र्द्ध गैस का बड़ा भंडार, कोईं मोबाइल बायोलॉजिकल लैब आदि वुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि अमेरिका ने बाद में खुद यह स्वीकार भी किया कि उसकी खुफि या जानकारी गलत थी। इराक पर हमले का आदेश देने वाले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी उस समय यही कहा था कि 'वे भी निराश हैं'। कईं अमेरिकी अधिकारी और पूर्व खुफि या प्रमुखों ने इसे खुफि या विफलता यानी ग्हात्त्गुाहम ग्त्ल भी कहा। परन्तु तब तक तो झूठ अफ वाह और दुष्प्रचार का निशाना सद्दाम हुसैन बन चुके थे। उसके बाद इसी बहाने इराक से तेल दोहन से लेकर इराक को अस्थिर व तबाह करने तथा वहां अमेरिकी सैन्य बेस बनाने तक के कईं खेल खेले गए। अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो पर भी मुख्य रूप सेनारको-टेररिज़्म, कोकीन आयात की साज़िश , मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों का क ब्ज़ा और उपयोग तथा मनी लॉन्ड्रग और हथियारों की साज़िश जैसे आरोप लगाए हैं। परन्तु उन्होंने मादुरो की गिरफ़्तारी के फ ौरन बाद ट्रंप ने कहा - कि अमेरिका वेनेज़ुएला को संचालित करेगा, खासकर इसके तेल भंडार और तेल उद्योग को।

टैरिफ से धमकाने वाले ट्रंप को झटका, 27 देशों ने किया बड़ा फैसला, भारत को क्या होगा फायदा?

भारत समेत अन्य देशों को ट्रेड टैरिफ लगाकर धमकाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोहरा झटका लगने वाला है। क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) 27 जनवरी को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा करेगा। इस डील से भारतीय उत्पादों को EU बाजारों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलेगी। ट्रंप के लिए 'दोहरे झटके' इसलिए है क् योंकि एक ओर एव भारत से निकटता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसके व्यापार समझौते पर तलवार लटक रही है।

EU अमेरिका के साथ व्यापार समझौता निलंबित कर सकता है

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति से जुड़े बीबीसी सूत्रों के मुताबिक, फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर सकती है।

EU में हैं 27 देश

याद रहे यूरोपीय संघ (EU) यूरोप के 27 देशों का एक साझा मंच है, जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह संगठन अपने सदस्य देशों के बीच शांति बनाए रखने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करता है, ताकि पूरे यूरोप में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

अमेरिका-EU के बीच पिछला व्यापार समझौता क्या था?

पिछले साल जुलाई में स्कॉटलैंड में हुए इस समझौते में अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर टैरिफ 30% से घटाकर 15% कर दिया था, बदले में यूरोपीय देशों ने अमेरिका में निवेश और निर्यात बढ़ाने पर सहमति दी। हालांकि, अब ट्रंप ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप पर दबाव बनाने के लिए अगले महीने से 10% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।

ट्रंप अब EU पर नए टैरिफ क्यों लगाने की धमकी दे रहे हैं?

ट्रंप की टैरिफ धमकियों से

यूरोपीय देश नाराज हैं। उन्होंने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये वही देश हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के ट्रंप के फैसले का खुलकर विरोध किया था।

किन यूरोपीय देशों पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाया है?

18 जनवरी को ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा, जिसमेंफरवरी से आठ देशों पर टैरिफ लगाया गया है, इनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा और यह बढ़ भी सकता है।" ये सभी देश ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ हैं और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया था।

ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए खतरा हैं, इसलिए वह इस पर तत्काल अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और लगभग 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है।

ग्रीनलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है?

ग्रीनलैंड लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा है

1979 से इसे स्वायत्तता प्राप्त है

विदेश और रक्षा मामलों में डेनमार्क निर्णय लेता है

डेनमार्क नाटो का सदस्य है, इसलिए ग्रीनलैंड को NATO सुरक्षा प्राप्त है

नमार्क नाटो (NATO) का सदस्य होने के कारण ग्रीनलैंड को इस संधि के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

यूरोपीय देशों की ट्रंप की टैरिफ नीति पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के फैसले का ब्रिटेन और फ्रांस ने विरोध किया, फ्रेंच विदेश मंत्री ने टैरिफ को 'ब्लैकमेलिंग' करार दिया। इस बीच, 27 जनवरी को होने वाले भारत-एव FTA से दोनों देशों को बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय व यूरोपीय उत्पादों को कम या शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा।

भारत-एव FTA से दोनों पक्षों को क्या फायदा होगा?

इसके साथ ही, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया है, जो वैश्विक व्यापार में जटिलताओं को बढ़ाता है।

डराता रहा पानी-सरिया-अंधेरा...कुहासे में डूबा सिस्टम और गड्ढे में समा गया युवराज

(जीएनएस)।

नोएडा सेक्टर 150 की उस रात को लोग कुहासे की रात कह रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उस रात धुंध सड़कों पर नहीं, पूरे सिस्टम की आंखों पर छाई हुई थी। 27 साल का युवराज मेहता, जो दिनभर कोड लिखकर अपने भविष्य के सपने बुनता था, उसी सिस्टम के गड्ढे में समा गया जिसे हम विकास कहते नहीं थकते। गुरुग्राम से लौटते वक्त उसकी कार एक ऐसे पानी भरे गड्ढे में गिरी, जिसे किसी ने गड्ढा मानने की जरूरत ही नहीं समझी थी।

बरसात का पानी, खुले लोहे के सरिए, टूटी दीवार और लापरवाही से छोड़ी गई एक कंस्ट्रक्शन साइट। यह सब किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के सबसे मॉडर्न कहे जाने वाले इलाके की हकीकत थी। युवराज कार की छत पर चढ़ा रहा, सांसें गिनता रहा और पिता को फोन कर आखिरी उम्मीद के साथ चिल्लाता रहा। सिस्टम ने मानों कान-आंख ही बंद कर लिए हों। सुबह जब जवाब आया, तब सिर्फ एक लाश बची थी।

इसे हादसा कहना भी अब एक तरह का मजाक लगता है। पुलिस आई, अग्निशमन दल आया, एसडीआरएफ भी आई, लेकिन सबके पास एक न एक बहाना था। पानी ठंडा है, नीचे सरिया है, अंधेरा है, रिस्क है। आपदा राहत के नाम पर करोड़ों के बजट वाले विभाग के पास एक लंबी रस्सी तक नहीं थी। उस रात सबसे बहादुर कोई अफसर नहीं, बल्कि एक डिलिवरी बॉय मोरिंदर निकला, जिसने जान जोखिम में डालकर पानी में छलांग लगा दी। युवराज बच नहीं सका, लेकिन इतिहास अगर ईमानदार हुआ तो उस डिलिवरी बॉय को बहादुर और सिस्टम को कायर जरूर लिखेगा।

युवराज की लाश तो निकाल ली गई, लेकिन सवाल जिंदा रह गए। थोड़ी सी मुस्तैदी होती, थोड़ी सी इंसानियत होती, तो शायद एक पिता का बेटा आज जिंदा होता। मौत के बाद बिल्डर गिरफ्तार हुआ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटाए गए और अब शायद जांच, इंक्वायरी और फाइलें चलेंगी। मगर जिनके अधीन पूरा प्रशासन, एसडीआरएफ और

व्यवस्था आती है, उन पर सवाल उठाना अब भी असुविधाजनक माना जा रहा है।

सेक्टर 150 को कभी रख्नङ्ग१३२ ज्ञ३८ बनाने का सपना दिखाया गया था। आज वहां अपार्टमेंट कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। आधे से ज्यादा मकान बिना रजिस्ट्रेशन बिक रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ उस बिल्डर का नहीं जिसने पानी भरा बेसमेंट खुला छोड़ा, सवाल उस अथॉरिटी का भी है, जिसने उसे इजाजत दी। सवाल उस दीवार का भी है, जो टूटी और फिर कभी बनाई नहीं गई? सवाल उस फ्ळड का भी है, जिसने ट्रक और ड्राइवर को लाइसेंस दिया? सवाल उस रअ्नक्का भी है जिसे तैरना नहीं आता और उस फायर ब्रिगेड का भी, जिसके पास रस्सी नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युवराज की जगह अगर कोई बड़ा नेता, अफसर या वीआईपी होता तो भी यही तमाशा होता? क्या तब भी पानी ठंडा लगता, सरिए डराते और अंधेरा आड़े आता? युवराज कोई खास आदमी नहीं था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।

युवराज एक नाम नहीं, एक आम आदमी है। वही आम आदमी जो नमक से लेकर सैलरी तक हर चीज पर टैक्स देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिसकी जान की कीमत शून्य हो जाती है। उस रात कुहासा सिर्फ मौसम का नहीं था, वह हमारी व्यवस्था की सोच का था। और जब तक यह

भारतीय टी20 टीम ने नए साल के पहले टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी शिकस्त दी

भारतीय टी20 टीम ने नए साल के पहले टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी शिकस्त दी है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया और फिर कसी हुई गेंदबाजी के दम पर कीवी टीम को लक्ष्य से काफी दूर रोक दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत ने बनाए 238 रन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भारत ने साल 2023 में कीवियों के खिलाफ 234 रनों का स्कोर बनाया था, जिसे आज अभिषेक शर्मा (84)

और रिंकू सिंह (44*) की तूफानी पारियों के दम पर पीछे छोड़ दिया गया।

190 रन ही बना सकी न्यूजीलैंड

लक्ष्य के दबाव में बिखरी टीम 239 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले से ही दबाव बनाए रखा। हालांकि, मध्यक्रम में कीवी बल्लेबाजों ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन रन-रेट का बढ़ता दबाव उनके विकेट गिरने का मुख्य कारण बना। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी।

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने किया। गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को कभी भी मैच में हावी होने का मौका नहीं दिया। विशेषकर डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का बेहतरीन मिश्रण किया। अगले मुकाबले की तैयारी इस बड़ी जीत ने न केवल भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों को भी पुख्ता किया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी टीम के इस संतुलित प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आए।

अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी (शुक्रवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम जहाँ वापसी की कोशिश करेगी, वहीं भारत की नजरें अपनी बढ़त को दोगुना करने पर टिकी होंगी।

अमेजन ने भारत में ऑल-न्यू इको शो 11 और फोर्थ-जनरेशन इको शो 8 का लॉन्च किया

लखनऊ, 21 जनवरी 2026: आज अमेजन ने भारत में एलेक्सा के साथ अपने ऑल-न्यू इको शो 11 और फोर्थ जनरेशन इको शो 8 स्मार्ट डिस्प्ले पेश किए। इन डिवाईसेज में ऑल-न्यू ऑडियो आर्किटेक्चर और डेल्लरील्लरी कस्टम सेंसर प्लेटफॉर्म है। साथ ही एज-टू-एज डिस्प्ले और थिन बेजेल के साथ इन्हें बिल्कुल नया डिजाईन दिया गया है। ये डिवाईस डीप बेस और स्पष्ट आवाज के साथ स्मार्ट होम रूटीन को आसान बना देती हैं। इनमें मोशन, प्रेजेंस और तापमान सेंसर दिए गए हैं। इको शो 11 और इको शो 8 क्रमशः 11 इंच और 8.7 इंच का व्यूईंग एरिया प्रदान करते हैं।

इको शो 11 और इको शो 8 में ऑन-स्क्रीन टच कंट्रोल या एलेक्सा को हैंड्स-फ्री वॉईस कमांड देकर स्मार्ट होम रूटीन संचालित किए जा सकते हैं। कंपैटिबल ऐप्स से ऑडियो-विज्युअल कंटेंट का आनंद लिया जा सकता है। कैलेंडर तथा शॉपिंग लिस्ट संभालने तथा रेसिपी आदि देखने जैसे दैनिक काम आसानी से किए जा सकते हैं।

दिलीप आर.एस., डायरेक्टर और कंट्री मैनेजर, अमेजनडॉटइन डिवाइसेस इंडिया ने कहा, ह्लइको शो 11 और इको शो 8 फैमिली शेड्यूल में तालमेल बनाने, स्मार्ट होम मैनेज करने, और व्यस्त दिनचर्या का प्रबंधन करने जैसे सभी काम संभाल सकते हैं। ये डिवाइस होम असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। ग्राहकों को ऑर्गनाइज्ड और कनेक्टेड रखती हैं, तथा उनके अनुरूप खुद को ढाल लेती हैं। ये सभी रूटीन काम संभाल लेती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा जरूरी कामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं डेल्लरील्लरी टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड ऑटोमेशन, नई ऑडियो अनुभव और एलेक्सा के साथ सुगम हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल के साथ इन डिवाइसेज को ग्राहकों के जीवन का हिस्सा बनते देखने के लिए उत्साहित

हूँ।ह्व

एडवांस्ड होम ऑटोमेशन बढ़ाता है सुविधा और आराम

इको शो 11 और इको शो 8 में कस्टम डिजाईन की अे3 ढ१ङ्क सिलिकॉन चिप दी गई है, तो बहुत तेज परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। इस सिलिकॉन चिप के साथ कस्टम सेंसर प्लेटफॉर्म, डेल्लरील्लरी है, जो एंबियंट अक के लिए बनाया गया है। यह कई सेंसर और सिग्नल्स का उपयोग करता है, जिनमें 13 मेगापिक्सल (एम.पी) का कैमरा, ऑडियो, अल्ट्रासाउंड वाई-फाई राडार, एक्सेलेरोमीटर और वाई-फाई सीएसआई शामिल हैं, जो व्यक्तिगत, प्रोएक्टिव और मददगार एलेक्सा अनुभव संभव बनाते हैं।

इससे ऑटोमेटेड प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं, जैसे जब कोई कमरे में प्रवेश करता है, तो ऑटोमेटेड लाईट अपने आप जल जाती हैं, या जब तापमान एक निश्चित स्तर पर पहुँच जाता है, तब तापमान पर आधारित दिनचर्याएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। ग्राहक एलेक्सा ऐप की मदद से स्मार्ट होम रूटीन स्थापित कर सकते हैं।

अधिकतम व्यूईंग एरिया और एंबियंट विज्युअल्स का आनंद लें

इको शो 11 और इको शो 8 में क्रमशः 11 ईंच फुल ऌऊ और 8.7 ईंच ऌऊ एज-टू-एज ग्लास डिस्प्ले दिए गए हैं। ये विस्तृत कलर्स के साथ शार्प पिक्चर प्रदान करते हैं। नए डिजाईन को ज्यादा स्लीक बनाया गया है। इसमें 3ऊ-निट फैब्रिक के साथ थिन बेजेल्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ा व्यूईंग एरिया मिल सके। साथ ही, एंबियंट विज्युअल वातावरण के अनुरूप अनुकूलित होकर आरामदायक व्यूईंग प्रदान करता है। इसके हाई डेफिनिशन डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, जो सेंटर्ड ऑटो-फ्रेमिंग और नॉईज रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों और परिवार से स्पष्ट वीडियो कॉल और बातचीत संभव बनाते हैं, जो एलेक्सा ऐप या इको स्मार्ट डिस्प्ले के माध्यम से संभव होती है।

जितेंद्र सिंह मीडिया राउंड टेबल पर पत्रकारों से रूबरू हुए-कहा उन्होंने स्पष्ट किया कि पारित परमाणु विधान पर 'कड़े समय सीमाओं' के बिना, उचित जांच के बाद नियम अधिसूचित किए जाएंगे

परमाणु ऊर्जा सुधारों में निर्णायक मोड़ पर भारत, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य: डॉ. जितेंद्र सिंह

सरकार सावधानीपूर्वक परमाणु नियम बनाएगी; सुरक्षा और संरक्षण अटल: डॉ. जितेंद्र सिंह

गगनयान मानवरहित मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले, 2026 की दूसरी छमाही में संभावित: डॉ. जितेंद्र सिंह

₹1 लाख करोड़ आरडीआई कोष प्रयोगशाला से बाजार तक संक्रमण को तेज करेगा; पहली किश्त शीघ्र अपेक्षित, डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायतें, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम निर्णायक मोड़ पर है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सुधार किए जा रहे हैं, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को कायम रखा जा रहा है।

मीडिया राउंड टेबल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति से जुड़े व्यापक मुद्दों पर, मंत्री ने कहा कि सरकार हाल ही में पारित परमाणु विधान के तहत विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि "कड़े समय सीमाओं" के बिना, उचित जांच के बाद नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा संरक्षण, हितधारकों की चिंताओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया ढांचा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल देगा। "हम गैर-सरकारी भागीदारी को खोल रहे हैं, जिसमें निजी खिलाड़ी भी शामिल हैं, बिना आवश्यक संरक्षणों पर समझौता किए," उन्होंने कहा। मंत्री ने कहा कि एक बार नियम लागू होने पर, अधिनियम के तहत कल्पित वैधानिक निकाय, जैसे सशक्त परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक इकाई के रूप में और परमाणु ऊर्जा निवारण आयोग, को कानून में पहले से निर्धारित संरचना और जनादेश के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

लागत संबंधी चिंताओं पर, मंत्री ने स्पष्ट किया कि जबकि हल्के जल रिएक्टर वर्तमान में स्वदेशी दाबित

भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की तुलना में अधिक महंगे हैं, लेकिन पैमाने, विनिर्माण के स्थानीयकरण और घरेलू भागीदारी में वृद्धि के साथ लागत कम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को खोलना बड़े निवेश आकर्षित करने और दक्षता लाने का भी उद्देश्य है।

दायित्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि संचालक-आपूर्तिकर्ता दायित्व ढांचा यथावत है। संचालकों और आपूर्तिकताओं के बीच कोई भी संविदात्मक व्यवस्था अनुमत है, लेकिन सरकार ऐसी समझौतों का पक्षकार नहीं होगी।मंत्री ने विधान पारित होने के बाद घरेलू निजी खिलाड़ियों और विदेशी सहयोगियों दोनों से प्रोत्साहनजनक रुचि पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया भारत के परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र और दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति में वैश्विक विश्वास को दशार्ती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल के प्रक्षेपण असफलताओं से भारत की विश्वसनीयता प्रभावित होने के सुझावों को खारिज कर दिया। "हर अंतरिक्ष मिशन की कठोर समीक्षा की जाती है। हम इसे विश्वसनीयता की हानि के रूप में नहीं देखते, विदेशी उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण सेवाओं के लिए कतार में लगे रहते हैं," उन्होंने कहा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि पिछले एक दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सरकारी समर्थन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्रमुख विभागों के बजट दोगुने से अधिक हो गए हैं। इसी समय, अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर-सरकारी इकाइयों के लिए खोलने से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था दृश्यमान और जीवंत बनी है, जो लगभग 8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और आने वाले वर्षों में 20-25 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

गगनयान कार्यक्रम पर अपडेट देते हुए, मंत्री ने कहा कि मानवरहित जी1 मिशन 2027 में प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले होगा, हालांकि यह 2026 की दूसरी छमाही में हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान अत्यधिक सावधानी और नौसेना सहित बहु-एजेंसी समन्वय की मांग करती है, ताकि सुरक्षित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर दिया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शासन और जनकल्याण के लिए उपयोग है, जो गति शक्ति के तहत अवसंरचना निगरानी, दूर चिकित्सा और कृषि से लेकर स्वामित्व कार्यक्रम के तहत ड्रोन-आधारित भूमि मानचित्रण तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि इन अनुप्रयोगों का व्यापक सामाजिक प्रभाव होने के बावजूद अक्सर इनकी रिपोर्टिंग कम होती है।

₹1 लाख करोड़ के कोष वाले अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष पर, मंत्री ने कहा कि महीने के अंत तक लगभग ₹4,000-5,000 करोड़ की पहली किश्त जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने सूचित किया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बायरैक) को द्वितीय स्तर के कोष प्रबंधकों के रूप में चिह्नित किया गया है ताकि पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आरडीआई कोष प्रयोगशाला अनुसंधान और बाजार-तैयार प्रौद्योगिकियों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं, जहां भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ कुछ चुनिंदा देशों में से एक है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में व्यापार की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र और ओडिशा के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में व्यापार की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

(जीएनएस)।

व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा (एनएलयूओ) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि केंद्र के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) चेयर्स कार्यक्रम के तत्वावधान में कटक स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा परिसर में "वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका" विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन में ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिरजा प्रसन्ना

और प्रसन्ना सतपथी मुख्य अतिथि के रूप में तथा प्रोफेसर एन.एल. मित्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष राजदूत उजल सिंह भाटिया भी मौजूद थे।

सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय सचिवालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वर्नर ज्डौक; शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉ. कौशिक देब; व्यापार और निवेश कानून केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा; और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान में व्यापार और सतत विकास की निदेशक सुश्री एलिस टिपिंग ने विशेष संबोधन दिए।

सम्मेलन में हुई चर्चाओं का केंद्र बिंदु अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के संगम पर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भूमिका थी। उच्च स्तरीय तकनीकी सत्रों में हरित औद्योगिक नीति, सतत व्यापार ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियां, नियामक प्रथाएं, कार्बन प्रशासन और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रत्येक पैनल चर्चा का समापन संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्रों के साथ हुआ, जिससे वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित हो सका। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षा जगत और नीति-निर्माण निकायों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने जलवायु और सतत विकास के उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को संरेखित करने पर अपने विचार साझा किए, जिससे नीतिगत संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक रचनात्मक मंच के रूप में सम्मेलन की भूमिका रेखांकित हुई।

बिहार की विद्युत वितरण कंपनी देशभर में सर्वश्रेष्ठ,नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मिला स्वर्ण पुरस्कार

(जीएनएस)।

बिहार की बिजली वितरण कंपनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन (एआईडीए) ने "डिजिटल पेमेंट में उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार" के लिए एनबीपीडीसीएल को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस (EDICON) 2026 के दौरान माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्रीमनोहर लाल ने ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकमनोज कुमार सिंह (भा.प्र.से) को पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री ने अळ&उ हानि में उल्लेखनीय कमी और वितरण कंपनियों की वित्तीय

स्थिति में सुधार के लिए बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियां नागरिकों तक सेवा पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि और डिजिटल सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कॉन्फ्रेंस के दौरान "स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण का प्रभावी उपयोग" सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा सचिव ने कहा, "स्मार्ट मीटर का उपयोग न केवल राजस्व संग्रहण बल्कि उससे प्राप्त हो रहे डाटा के विश्लेषण के माध्यम से संचालन क्षमता को मजबूत करने एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।" राज्य में स्मार्ट मीटर के व्यापक अधिष्ठापन पर उन्होंने बताया, "वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में बिहार में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2021 में राज्य की दोनों वितरण कंपनियां घाटे में थीं लेकिन विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन, डिजिटल पेमेंट में सुधार और बेहतर सेवा देने की प्रतिबद्धता के चलते दो साल के भीतर, वर्ष 2025 में, दोनों कंपनियों ने लाभ दर्ज किया।"

भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक नाय प्यी ताव में आयोजित

भारत-म्यांमार संयुक्त वार्ता ने कनेक्टिविटी, व्यापार सुविधा और एआईटीआईजीए कार्यान्वयन की समीक्षा की

भारत-म्यांमार व्यापार 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना दोनों पक्षों का लक्ष्य

(जीएनएस)।

भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की नौवीं बैठक आज म्यांमार के नाय प्यी ताव में आयोजित की गई। म्यांमार गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री यू मिन मिन और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में दोनों पक्षों के संबंधित हितधारक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक में कनेक्टिविटी में सुधार, बाजार पहुंच का विस्तार, वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना, सीमा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन, सीमा व्यापार चौकियों को पुनः खोलना, रुपया-क्यात व्यापार निपटान प्रणाली को बढ़ावा देना और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के लाभों को अधिकतम करना सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। म्यांमार पक्ष ने भारत सरकार द्वारा म्यांमार के निर्यात, विशेष रूप से दालों और फलियों के क्षेत्र में, खुले और सहायक नीतिगत वातावरण बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त किया।

आपसी विकास को गति देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, जिसमें वस्त्र, परिवहन और कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन, जहाजरानी, बिजली, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्वास्थ्य, औषधि और कृषि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और आपसी समर्थन एवं सहयोग के ढांचे को मजबूती मिल सकती है।

बैठक में सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए तामू-मोरेह और रही-जोखावथर सीमा व्यापार चौकियों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की गई। भारतीय पक्ष ने इन स्थलीय सीमा चौकियों को शीघ्रता पूर्वक फिर से खोलने के अपने अनुरोध को दोहराया। दोनों पक्षों ने व्यापार दक्षता को और बढ़ाने के लिए तामू में एक एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के दौरान 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक मजबूत और सकारात्मक वृद्धि का संकेत है। आगे विस्तार की अपार संभावनाओं को देखते हुए, दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने आसियान-भारत व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, ताकि इसे सरल, संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यापार को सुगम बनाने वाला बनाया जा सके।

इतने कम दाम पर मिलेगी बिजली, फडणवीस सरकार ने बनाई नई बिजली कंपनी

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने किसानों के लिए एक समर्पित बिजली कंपनी स्थापित की है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कंपनी का उद्देश्य किसानों को स्थायी और कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा दावेस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए दी। सीएम ने बताया कि किसानों को बिजली आपूर्ति करन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बिजली कंपनी बनाई है। इस बिजली वितरित प्रणाली के माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से लगभग 16 गीगावॉट बिजली उत्पन्न की जाएगी। उन्होंने बताया इस साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

महाराष्ट्र में किसानों को कितनी सस्ती मिलेगी बिजली?

कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग

को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के एक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएम ने बताया कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के किसानों को अभी 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत आने वाले दिनों में राज्य के किसानों को महज 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली का दाम देना पड़ेगा।

कब मिलेगी महाराष्ट्र के किसानों को सस्ती बिजली?

पूर्व के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (अक्कह) के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। फडणवीस ने बताया कि राज्य ने दिसंबर 2026 तक विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं के लिए 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नई ऊर्जा कंपनी के जरिए वर्ष 2026 के अंत तक महाराष्ट्र के हर किसान तक सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करेगी।

फडणवीस ने कहा, "यह पहल किसानों को स्वच्छ ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई करने में सक्षम बनाएगी। सौर पंप एक बड़ी वित्तीय राहत भी प्रदान करेंगे, क्योंकि किसानों को अगले 25 वर्षों तक इसके लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।"

आईआईसीडीईएम -2026 का संचालन शुरू हुआ

ईसीआई ने एक औपचारिक स्वागत समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का स्वागत किया; इस कार्यक्रम में वृत्तचित्र श्रृंखला "इंडिया डिसाइड्स" की झलकियां भी दिखाई गईं

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का तीन दिवसीय सम्मेलन, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026, आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ।

विशेष रूप से आयोजित एक स्वागत समारोह में, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों (ईसी) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सम्मेलन का शुभारंभ एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ हुआ, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के प्रतिनिधियों, 27 देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और देश भर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) सहित लगभग 1,000 लोगों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में निर्वाचन आयोगों के कार्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव कराता है, जिसकी जनसंख्या 1.5 अरब है।

निर्वाचन आयोग के डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने नागरिकों द्वारा ईएमबी में रखे गए विश्वास को अनमोल बताते हुए कहा कि हर चुनाव के केंद्र में एक नागरिक होता है, जिसे विश्वास होता है कि उसकी पसंद का सम्मान किया जाएगा और इसकी रक्षा करना ईएमबी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में, निर्वाचन आयोग के डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि आईआईसीडीईएम-2026 उन ईएमबी, शोधकताओं, छात्रों और पेशेवरों को एक साथ लाता है जो चुनावों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और अपने-अपने संस्थानों में योगदान करते हैं।

आईआईसीडीईएम -2026 के विषय पर आईआईआईडीईएम के महानिदेशक श्री राकेश वर्मा ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय, 'एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र', इस बात की व्यापक और बहुआयामी समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में लोकतंत्र को क्या प्रदान करना चाहिए।

प्रतिभागियों ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से निर्मित आगामी वृत्तचित्र श्रृंखला "इंडिया डिसाइड्स" की झलकियां देखीं। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रबंध निदेशक श्री अर्जुन नोहवार ने अपने भाषण में कहा कि यह वृत्तचित्र श्रृंखला आकर्षक दृश्यों के माध्यम से एक ऐसी संस्था के कामकाज को दर्शाती है, जिसके पास दुनिया भर में सबसे जटिल दायित्वों में से एक है।

एसटीपीआई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में 'दूरसंचार में एआई' विषय पर इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व-शिखर कार्यक्रम आयोजित

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के सहयोग से बुधवार आज नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर स्थित एसटीपीआई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में "दूरसंचार में एआई" विषय पर इंडिया झ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व-शिखर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, ओईएम, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) किस प्रकार दूरसंचार नेटवर्क, सेवा वितरण और ग्राहक जुड़ाव के भविष्य को नया आकार दे रही है। यह कार्यक्रम भारत के एआई-संवर्धित डिजिटल अवसंरचना की ओर संक्रमण के दौरान वास्तविक उपयोग के मामलों, नीतिगत विचारों और कार्यान्वयन चुनौतियों को प्रदर्शित करने

के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

कार्यक्रम का शुभारंभ टीआरएआई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी, टीआरएआई के सदस्य श्री रितु रंजन मित्तर, टीआरएआई के सदस्य डॉ. एमपी तंगीराला, टीआरएआई के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी, एसटीपीआई के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार और आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में एसटीपीआई के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार ने स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग को जोड़ने वाले एआई-आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जिसे हम कभी एक साधारण पाइप कहते थे, वह अब एक बुद्धिमान पाइप में बदल गया है।" उन्होंने यह भी बताया कि आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिम्मेदार और प्रभावशाली एआई अपनाने के लिए एक समग्र और भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करेगा। इसके बाद टीआरएआई के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी ने सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में एआई के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और नैतिक सुरक्षा उपायों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले नियामक ढांचों

संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित सम्पन्न पेंशन पोर्टल, उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत हुआ

उमंग पर संपन्न के एकीकरण ने दूरसंचार विभाग के देश भर के लगभग 4 लाख पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ और जीवन प्रमाण पत्र की वैधता स्थिति की सुगम जांच को सक्षम बनाया

(जीएनएस)।

संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित सम्पन्न पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग (यूनिफायड मोबाइल एप्लिकेशन फॉरन्यू एज गवर्नेंस) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इस पहल से पेंशनभोगियों को उमंग वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर और जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) की वैधता स्थिति प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर समय उपलब्ध रहे।

दिल्ली के प्रधान संचार लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) श्री आशीष जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एकीकरण पेंशनभोगियों के लिए सुविधा बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन संबंधी जानकारी की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से इन सेवाओं की उपलब्धता, हाल ही में किए गए डिजिलॉकर एकीकरण के साथ मिलकर, सभी पेंशनभोगियों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

उमंग एक एकल एकीकृत मंच है, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन और वेब

पोर्टल शामिल हैं, जिसके माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं को कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, यह एंड्रॉयड, आईओएस और वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे गूगल प्लेस्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से उमंग एप्लिकेशन का उपयोग करें और आधार कार्ड के माध्यम से प्रमाणीकरण करें।

संपन्न के बारे में: संपन्न (सिस्टम फॉर एकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) विभाग का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पेंशन प्रशासन और संबद्ध वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित, यह प्रणाली-केंद्रित प्रशासन से पेंशनभोगी-केंद्रित शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों को अपने उचित लाभों का दावा करने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

संपन्न ने पेंशन प्रक्रिया के संपूर्ण चक्र—मामलों की शुरूआत और प्रक्रिया से लेकर ई-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने, वितरण, लेखांकन, मिलान, वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा में सहायता और शिकायत निवारण तक- को डिजिटल कर दिया है। पेंशनभोगी अब सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करते हैं, जिससे बैंकों या सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है; वे भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, ई-पीपीओ जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या पते जैसे बदलावों का अनुरोध कर सकते हैं और घर बैठे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विभाग हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन भी संचालित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न झ सम्पन्न सेवाओं को एक्सेस करने के लिए उमंग

1. उमंग क्या है?

उमंग एक एकल एकीकृत मंच (मोबाइल ऐप + वेब पोर्टल) है, जिसके माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं का लाभ कभी भी, कहीं भी उठाया जा सकता है। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और एंड्रॉयड, आईओएस और वेब पर उपलब्ध है।

2. उमंग को कैसे एक्सेस करें?

ए. वेब पोर्टल के माध्यम से

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://web.umang.gov.in/

2. ऊपर दिए गए लॉगिन/रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

ब. मोबाइल ऐप के माध्यम से

1. गूगल प्लेस्टोर (एंड्रॉयड) या एप्पल स्टोर (आईओएस) से उमंग ऐप डाउनलोड करें।

सीटीआईएल और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने गांधीनगर में विधि एवं अर्थशास्त्र पर 9 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

सम्मेलन कानून, अर्थशास्त्र एवं व्यापार नीति पर विचार-विमर्श के लिए नीति निमार्ताओं, शिक्षाविदों व उद्योग जगत को एक साथ लाया

(जीएनएस)।

सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (सीटीआईएल) ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के सहयोग से, जीएनएलयू के 'सेंटर फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स', 'सेंटर फॉर एम्पेरिकल एंड एप्लाइड रिसर्च इन लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज' और 'सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज' के माध्यम से, गांधीनगर में '9वें अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन' (शासन और समावेशी सार्वजनिक नीति का अनुभवजन्य और अनुप्रयुक्त विधि और अर्थशास्त्र) का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

इस सम्मेलन में कानून और अर्थशास्त्र के इंटरफेस से जुड़े प्रमुख मुद्दों की जांच की गई, जिसमें नीति निमार्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और उद्योग हितधारकों के दृष्टिकोण से व्यापार नीति की चुनौतियों को शामिल किया गया। इसमें पैनल चर्चा, तकनीकी सत्र और विशेषज्ञ पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। तीन दिनों के दौरान, इस सम्मेलन ने व्यापार नीति, शासन और समावेशी सार्वजनिक नीति को आकार देने वाले समकालीन कानूनी और आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कानूनी शिक्षा जगत, न्यायपालिका, कानूनी अभ्यास, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़ी प्रमुख हस्तियों को एक मंच पर लाया।

सीटीआईएल ने "बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) संधि (टीकेजीआर संधि) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौता" तथा "स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापार के प्रति भारत का दृष्टिकोण: उभरती चुनौतियाँ और अंतराल" पर दो पैनल चचाओं का नेतृत्व किया।

उद्घाटन सत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और भारत के महान्यायवादी, श्री आर. वेंकटरमणी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने मुख्य भाषण में, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को न केवल कानून लागू करना चाहिए, बल्कि कानूनी व्याख्याओं के आर्थिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, श्री आर. वेंकटरमणी ने नीति निमार्ताओं के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं और अनुभवजन्य मॉडलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस सम्मेलन में भारत भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कानून और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ-साथ जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया के म्योंगजी विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, जापान के तोम्योंगजी होकू विश्वविद्यालय और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) सहित प्रमुख विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं ने भी विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ के हेड, प्रो. (डॉ.) जेम्स जे. नेडुम्परा ने "सेवा व्यापार और व्यावसायिक गतिशीलता" पर अपने विशेषज्ञ पूर्ण सत्र के भाषण में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते और भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसमें प्राकृतिक व्यक्तियों की अस्थायी आवाजाही से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का विशेष संदर्भ दिया गया। उन्होंने सेवाओं की डिलीवरी के सीमा-पार तौर-तरीकों, वीजा संबंधी नियामक बाधाओं और पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) की बढ़ती प्रासंगिकता पर भी विचार साझा किए।

सीटीआईएल द्वारा आयोजित एक पैनल ने डब्ल्यूआईपीओ टीकेजीआर संधि और डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स समझौते के बीच अंतसंबंधों की जांच की। सत्र के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) उन्नत पंडित ने

ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर बनकर तैयार हुआ 6 लेन पुल, उद्घाटन की डेट भी हो गई तय

(जीएनएस)।

असम की राजधानी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला सिक्स-लेन ब्रिज अब तैयार हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा यह लगभग 1,600 मीटर लंबा पुल फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह परियोजना न केवल असम की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की महत्वाकांक्षी अरङ्ग 2.0 विकास योजना का यह अहम हिस्सा है।

अभी गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी पहुंचने में फेरी या पुराने पुलों के जरिए करीब एक घंटे तक का समय लग जाता है। सिक्स-लेन ब्रिज चालू होने के बाद इस सफर में मात्र 10 से 15 मिनट में लगेंगे। इससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही,

व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

- गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी सिक्स-लेन ब्रिज इस विजन को जमीन पर उतारने का बड़ा उदाहरण है। इस पुल के जरिए ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर बसे क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो सकेगा।

- उत्तर गुवाहाटी में नए रिहायशी प्रोजेक्ट, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है। आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले यह पुल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसका सीधा असर सत्तारूढ़ सरकार की छवि पर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब चुनावी मुद्दा है और असम की राजनीति में इसकी परंपरा भी रही है। ऐसे में अरङ्ग 2.0 के तहत पूरा होने जा रहा यह ब्रिज सरकार के विकास एजेंडे को मजबूत आधार दे सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा विकास प्रोजेक्ट को लेकर खासे मुखर रहे हैं।

गुवाहाटी का ट्रैफिक होगा कम

गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी सिक्स-लेन ब्रिज न सिर्फ यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि असम के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को भी नई दिशा देगा। फरवरी 2026 तक इसके उद्घाटन के साथ ही ब्रह्मपुत्र पर यह पुल राज्य के विकास की पहचान बन सकता है।

पीएम मोदी के निर्देश पर बदली जल शक्ति मंत्रालय के तहत इस मिनी रत्न कंपनी की किस्मत, घाटे से उबरी, करोड़ों बचाए

नई दिल्लीः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वापकोस (WAPCOS) और इसकी सहायक इकाई ठढउउ का कायापलट हो गया है. इन कंपनियों ने घाटे और विवादों से उबरना प्रारंभ कर दिया है. केवल तीन महीनों में ही वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन प्रबंधन, कामकाज के क्षेत्र में बदलाव और नए व्यवसाय के मामले में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है. सरकारी सूत्रों के अनुसार कंपनी ने लंबित भुगतानों और बकाया वसूली में बड़ी सफलता हासिल की है जिससे वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है.

यह कंपनी जल संसाधन, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कंस्लटेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, खरीद-बिक्री और निर्माण कार्य में लगी है। यह बांध, जलाशय, सिंचाई, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन और बिजली परियोजनाओं पर विशेषज्ञता रखती है। हअढउडर 75 से अधिक देशों में सक्रिय है. दक्षिण एशिया और अफ्रीका में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है जहां यह एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं के साथ काम करती है.

पिछले कई वर्षों से यह लालफीताशाही, कुप्रबंधन, अनियमितताओं और घाटे का शिकार थी. बीच में यह प्रस्ताव भी आया कि इसका और एनपीसीसी का विलय कर दिया जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि इस कंपनी को घाटे से उबारा जाए ताकि अन्य सरकारी कंपनियों के लिए यह एक मिसाल बन सके. इसके बाद जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने तुरत फैसले करते हुए इसका कायापलट करने का काम शुरू किया. सूत्रों के अनुसार इस काम में वर्तमान सीएमडी शिल्पा शिंदे ने प्रमुख भूमिका अदा की है जिन्हें रजनी कांत अग्रवाल को हटाए जाने के बाद लाया गया था. यह कंपनी अपने पूर्व सीएमडी पर लगे गंभीर आरोपों के चलते विवादों से भी घिरी थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निदेर्शों और निगरानी के बाद इसकी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ है. हुआ कायापलट

कंपनी ने अब ₹484 करोड़ की वसूली की है और वेतन बिल में 60 करोड़ की वार्षिक बचत हुई. दिसंबर 2025 में दो वर्षों के अंतराल के बाद हअढउडर की वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। कंपनी ने कुल ₹484 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की, जबकि टरटए वेंडरों सहित विभिन्न देयकों का भुगतान भी पूरा किया गया. इसके अलावा गैर-तकनीकी संविदा कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने और बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली लागू करने जैसे कदमों से वेतन बिल में कमी लाकर कुल ₹60 करोड़ की वार्षिक बचत सुनिश्चित हुई.

किराये के दफ्तर खाली, गैर-लाभकारी कार्यालय बंद किए गए। इससे कुल बचत लाखों में पहुंच गई. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में किराये के दफ्तर खाली करने से ₹1.14 करोड़, पंचकुला, कंबोडिया और तुर्की स्थित गैर-लाभकारी कार्यालय बंद करने से ₹1.80 करोड़ की बचत की गई। वहीं कर्मचारियों से लफ्ध्र वसूली के रूप में ₹1.75 करोड़ की बचत दर्ज की गई। थर्ड-पार्टी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर कंपनी ने ₹46 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक बचत दर्ज की। इस तरह साल भर में सौ करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हुई है जिसका उपयोग कंपनी के विस्तार और कर्मचारियों के हित में किया जा रहा है. कंपनी के इतिहास में पहली बार फङ्ग३३ङ्गल्ल ढङ्ग'८ लागू की गई, जिसके तहत विदेशों में लंबे समय से तैनात 54 कर्मचारियों को वापस बुलाया गया और चयन प्रक्रिया के बाद नई तैनाती की गई. परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के लिए 200 से अधिक कर्मचारियों को परियोजनाओं पर स्थानांतरित किया गया. हालांकि इस कदम के बाद 52 कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दिया. कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 28 तकनीकी इकाइयों का विलय कर उन्हें 6 प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्गठित किया है. ये हैं - जल संसाधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, विद्युत, अवसंरचना, तृतीय पक्ष निरीक्षण और निर्माण.

गृहमंत्री अमित शाह गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र 'कल्याण' के शताब्दी अंक विमोचन

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र 'कल्याण' के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को संबोधित किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने लक्ष्मीनारायण मंदिर एवं मां गंगा के दर्शन और पूजन भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सनातन धर्म से आकांक्षा रखने वाला, दुनिया की समस्याओं के समाधान लिए भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है और इस भूमि से प्रेम करने वाला भारत और दुनिया का कोई भी व्यक्ति गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षो से सनातन धर्म की लौ को ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोडों लोगों

को भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया और इस रास्ते पर चलते हुए मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त किया। श्री शाह ने कहा कि पोद्दार जी ने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया। पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से हर व्यक्ति और परिवार के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा निर्मित करने का काम किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलती है। स्वावलंबी तरीके से सद्साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने किया है।

सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 22वां संस्करण

(जीएनएस)।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 21 जनवरी, 2026 को सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज (सीएपीएसएस) द्वारा आयोजित सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के 22वें संस्करण में उद्घाटन भाषण दिया। यह सम्मेलन भारतीय वायु सेना के पहले वायु सेना प्रमुख और वायु सेना के दूरदर्शी संस्थापकों में से एक एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के सम्मान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का विषय 'राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं' था, जिसका उद्देश्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों और अवसरों की बदलती प्रकृति पर संवाद तथा बौद्धिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना था।

इस संगोष्ठी में नीति-निमार्ता, प्रख्यात विद्वान, विशेषज्ञ और सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र हुए। इस सेमिनार का उद्देश्य तीव्र गति से हो रहे तकनीकी सुधारों और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के इस युग में भारत की सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्धारकों का विश्लेषण व सार्थक चर्चा करना था। इस आयोजन की प्रमुख चचाओं में "बहु-क्षेत्रीय अभियानों में राष्ट्रीय सुरक्षा की

अनिवार्यताएं" और "बहुध्रुवीय दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा की पुनर्कल्पना" जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहीं, जिनके माध्यम से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों एवं अवसरों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन, 19 जनवरी, 2026 से 26 जनवरी, 2026 तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के दूसरे चरण के अंतर्गत किया गया।

मंत्रालय के सचिव श्री तन्मय कुमार के नेतृ व में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति से नई दिल्ली के

इंदिरा पर्यावरण भवन स्थित मंत्रालय परिसर गूंज उठा। 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आयोजित किया जा रहा है।

इस आयोजन में सभी प्रतिभागी एक साथ मिलकर उन अद्वितीय छंदों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे, जो अपनी रचना के 150 साल बाद भी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के व्यापक राष्ट्रव्यापी स्मारक कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन की गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट बैठक

मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की

राज्य में ओलंपिक खेलों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को ऑस्ट्रेलिया आने का उच्चायुक्त का निमंत्रण

गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स बिजनेस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अलग एक इकोसिस्टम विकसित करेगी

रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में गुजरात की तीव्र प्रगति से ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त प्रभावित

रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का सहयोग देने की उत्सुकता व्यक्त की

गांधीनगर, 21 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फास्ट्रक्चर, आवास और अन्य स्पोर्ट्स सुविधाओं के दीर्घकालीन सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री के साथ भारत में

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ने गांधीनगर में की गई शिष्टाचार भेंट बैठक के दौरान यह तत्परता दर्शाई।

इस बैठक में आगामी 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले ओलंपिक खेलों के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन्फास्ट्रक्चर, आवास और अन्य सुविधाओं की तैयारी के लिए की जा रही कवायद को लेकर विस्तृत विचार - विमर्श हुआ।

उन्होंने ऐसे इन्फास्ट्रक्चर का खेल समाप्त होने के बाद आम लोगों के आवास, छात्रों के हॉस्टल तथा मैदानों के अन्य आयोजनों के लिए उपयोग करने की योजना का विवरण दिया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने ब्रिस्बेन में की जा रही इन तैयारियों के निरीक्षण के लिए गुजरात के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रण दिया। उन्होंने भूमिका दी कि गुजरात में विशेष रूप से स्विमिंग, पैरा एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहभागी होने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका उच्च प्रशिक्षण लाभ गुजरात के खिलाड़ियों को भी मिले और 2036 ओलंपिक में उज्ज्वल प्रदर्शन हो सके; इसके लिए उन्होंने संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ने की अपेक्षा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स बिजनेस और स्पोर्ट्स रिसर्च के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर एक संपूर्ण विशिष्ट इकोसिस्टम विकसित करने की जानकारी भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मार्च 2026 में होने वाले डीकिन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा वाइब्रेंट समिट में ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से राज्य के जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एपैरल एंड क्लोथिंग, लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को हुए लाभ का उल्लेख किया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त गुजरात द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में ली गई अग्रणी भूमिका से प्रभावित हुए। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का सहयोग गुजरात को देने की तत्परता व्यक्त की।

इतना ही नहीं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में सोलर रूफ टॉप के लिए 2000 लोगों की क्षमता के साथ ट्रेनिंग फैसीलिटी विकसित की जा रही हैं तथा इसमें विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती रुचि की भी उन्होंने प्रशंसा की।

इस शिष्टाचार भेंट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव श्री संजीव कुमार, सचिव श्री अजय कुमार, इंडेक्स्ट-सी के प्रबंध निदेशक श्री केयूर संपत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद आएंगे:राज्यमंत्री बृजेश सिंह के पिता को देंगे श्रद्धांजलि, उपमुख्यमंत्री पाठक भी पहुंचेंगे

देवबन्द, (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को देवबंद पहुंचेंगे। वह लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री बृजेश सिंह के पिता डॉ. राजकुमार रावत के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी राज्यमंत्री के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे।

राज्यमंत्री बृजेश सिंह के पिता डॉ. राजकुमार रावत का आकस्मिक निधन गत 13 जनवरी को हो गया था। उनकी रस्म तेरहवीं 25 जनवरी को होगी। निधन के बाद से जड़ौदा जट्ट गांव स्थित राज्यमंत्री के आवास पर राजनेताओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 3:30 बजे देवबंद

पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से 3:10 बजे रवाना होगा और 3:30 बजे देवबंद में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से वे कार द्वारा राज्यमंत्री बृजेश सिंह के जड़ौदा जट्ट स्थित आवास पर जाएंगे।

मुख्यमंत्री 3:40 बजे से 3:55 बजे तक आवास पर रुककर श्रद्धांजलि देंगे और शाम 4:00 बजे सरसावा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक गुरुवार सुबह करीब 10 बजे देवबंद पहुंचेंगे। वह भी राज्यमंत्री के आवास पर जाकर डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी मनीष बंसल, डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी आशीष तिवारी सहित अन्य अधिकारी जड़ौदा जट्ट गांव पहुंचे और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सफाई विभाग दिन भर जुटा रहा, और खुफिया विभाग भी चौकन्ना बना हुआ है।

डिजिटल इंडिया के भाषिणी प्रभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्थलाकृतिक डेटा के डिजिटलीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग-डीआईबीडी ने 20 जनवरी 2026 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इं टेलिजेंस आधारित वाक और भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग से भौगोलिक स्थानों के नामों के डिजिटलीकरण, लिप्यांतरण और मानकीकरण में सहयोग करना है। यह सहयोग राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के अनुरूप सटीक, बहुभाषी और मानकीकृत स्थान नामिकी डेटा संग्रह निर्माण में सहायक होगा।

भौगोलिक नामों के मानकीकरण और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग , राष्ट्रीय मानचित्रण प्रणाली में शामिल करने के लिए स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में स्थानों के नाम की जानकारी हेतु व्यापक जमीनी

सर्वेक्षण करता है। सहयोग के तहत, भाषिणी की वाक्-से-पाठ और भाषा प्रसंस्करण क्षमताओं के उपयोग से स्थानों के नाम ऑडियो रिकॉर्डिंग को संरचित डिजिटल पाठ में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे 16 लाख से अधिक स्थानों को कवर करने वाले व्यापक और प्रमाणित स्थलाकृतिक डेटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भाषिणी प्रभाग के बीच यह सहयोग राष्ट्रीय भौगोलिक नामकरण सूचना प्रणाली विकसित करने में सहायक होगा। इसके तहत क्षेत्र से एकत्रित ऑडियो (श्रव्‍ य) डेटा को स्थानीय भाषा लिपियों, देवनागरी, रोमन और अन्य प्रारूपों में संसाधित किया जा सकेगा, जिससे राष्ट्रीय मानचित्रों, डिजिटल प्लेटफार्मों और शासन प्रणालियों में समरूपता सुनिश्चित होगी। स्वचालित वाक पहचान, भाषा मानकीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को समेकित करने से स्थलाकृतिक नामकरण डेटा प्रसंस्करण की गति, सटीकता और व्यापकता में वृद्धि होगी।

इस पहल से स्थानों के नाम का ऑडियो दस्तावेजीकरण सुदृढ होगा और सही उच्चारण और स्थानीय भाषाई विविधताएं संरक्षित होंगी। साथ ही, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भू-नाम नियमावली और भारतीय मानक ब्यूरो-बीआईएस की कार्य संहिता के संरेखण द्वारा मानकीकरण व्यवस्थित होगा। इससे सर्व सुलभ मानचित्र, गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक सूचना प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले स्थान नामिकी डेटासेट की विश्वसनीयता बढेगी।

इस साझेदारी द्वारा डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग डेटा निर्माण, स्पष्टीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए अपने वाक और भाषा कृत्रिम बुद्धिमता पोर्टफोलियो की सहायता प्रदान करेगा, जिससे मानव वाक को उच्च गुणवत्तापूर्ण भौगोलिक भाषा डेटासेट में व्‍ यापक रूप से परिवर्तित करना संभव होगा। यह सहयोग सेवा प्रदान करने और निर्णय लेने में भाषाई सटीकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भाषिणी के राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रणालियों में भाषा एआई एकीकृत करने के

पशुधन सांख्यिकी पर तकनीकी समिति की दो दिवसीय वार्षिक बैठक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में होगी

(जीएनएस)।

सरकार का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), 22 और 23 जनवरी, 2026 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में पशुधन सांख्यिकी में सुधार के लिए टेक्निकल कमेटी ऑफ डायरेक्शन (टीसीडी) की सालाना बैठक आयोजित कर रहा है।

टीसीडी एक अहम टेक्निकल बॉडी है जो इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे (आईएसएस) स्कीम के तरीकों और लागू करने में गाइड करती है। यह स्कीम दूध, अंडे, ऊन और मांस जैसे मुख्य पशुधन उत्पादों के देश के उत्पादन का अनुमान लगाने का मुख्य सोर्स है। इस मीटिंग का मकसद प्रगति की समीक्षा करना, चुनौतियों का समाधान करना और भारत में मजबूत और भरोसेमंद पशुधन आंकड़ों के लिए भविष्य की योजना बनाना है।

बैठक का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री श्री के. अचन्नायडू गारू 22 जनवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे करेंगे। उद्घाटन समारोह में श्री कल सिंह, महानिदेशक (सांख्यिकी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चेयरमैन-टीसीडी, श्री बी. राजशेखर, आईएएस, पदेन विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, और श्री जगत हजारिका, सलाहकार, पशुपालन और डेयरी विभाग जैसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा, एमओएसपीआई, डीएऔरएफडब्ल्यू, आरबीआई, एफएओ और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसी विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।